दैनिक जागरण

मानवता का पहला पाठ उपकार की परंपरा से आरंभ होता है

राहुल का राजनीतिक दांव

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह घोषणा करके एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वह हर गरीब के खाते में एक निश्चित रकम जमा करेगी। रायपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी वाली अपनी भावी योजना का एलान भर नहीं किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह इस बारे में फैसला ले चुके हैं। उनकी मानें तो यह वह फैसला है जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। राहुल गांधी की यह घोषणा इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि अभी तक वह मोदी सरकार पर इसके लिए दबाव बनाए हुए थे कि वह किसानों के लिए कर्ज माफी की कोई योजना लेकर आए। वह केवल दबाव ही नहीं बनाए हुए थे, बल्कि मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करने की मुहिम भी छेड़े हुए थे। उनका यहां तक कहना था कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के लिए कर्ज माफी की कोई घोषणा नहीं करती तब तक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे। हालांकि मोदी सरकार राहुल गांधी के दबाव में आने के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों की किसान कर्ज माफी योजना को लालीपॉप कहकर खारिज कर रही थी, लेकिन इसी के साथ यह भी संकेत दे रही थी कि वह किसानों को राहत देने के लिए कोई बड़ी योजना लेकर आ सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के नीति-नियंता किसानों और अन्य गरीबों के लिए वैसी ही किसी योजना की रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए थे जैसी योजना लागू करने की घोषणा राहुल गांधी ने यकायक कर दी। ऐसा करके उन्होंने एक तरह से राजनीतिक बढ़त ले ली है। निःसंदेह इसका यह मतलब नहीं कि अब मोदी सरकार ऐसी कोई योजना लाने का विचार त्याग देगी, लेकिन अब अगर वह यह योजना लेकर आती है तो उसका श्रेय कांग्रेस खुद लेने की कोशिश करेगी। उसे केवल यही प्रचार करने का अवसर नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी के दबाव के कारण मोदी सरकार गरीबों की सुध लेने के लिए बाध्य हुई, बल्कि यह भी रेखांकित करने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष को गरीबों की कहीं अधिक परवाह है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि मोदी सरकार किसानों के साथ अन्य गरीबों के लिए ठीक वैसी ही कोई योजना लेकर आएगी या नहीं जिसकी मुनादी राहुल गांधी ने बजट सत्र शुरू होने के पहले ही कर दी, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसी के साथ उसे इसकी भी चिंता करनी होगी कि ऐसा कोई संदेश न जाने पाए कि उसने वह किया जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने दबाव बनाया। जो भी हो, राजनीतिक दांवपेच के फेर में किसानों और अन्य गरीबों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी वाली योजना लाने की घोषणा कर जो राजनीतिक बढ़त हासिल की उसका प्रतिकार मोदी सरकार चाहे जैसे करे, यह राहत की बात है कि आखिरकार राहुल गांधी यह मानते-समझते दिख रहे हैं कि किसान कर्ज माफी से किसी का और यहां तक कि किसानों का भी भला नहीं होता।

शक्ति प्रदर्शन

19 जनवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी 23 दलों के दो दर्जन से अधिक नेताओं को एकत्रित कर तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। इसके महज 13 दिन बाद ही वामपंथी दलों और खासकर माकपा अपनी ताकत दिखाने के लिए तीन फरवरी को उसी ब्रिगेड मैदान में रैली आयोजित कर रही है। वैसे वामपंथी दलों के लिए ब्रिगेड रैली कोई नई बात नहीं है। यह लगभग हर वर्ष होती आ रही है, परंतु इस बार कुछ खास है, क्योंकि वामपंथी दल ब्रिगेड मैदान को भरकर यह दिखाने की कोशिश में हैं कि उनकी ताकत बंगाल में कम नहीं हुई है। वहीं यह भी संदेश देने का प्रयास है कि सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी जो नहीं कर सकी वह वामपंथी दलों ने कर दिखाया, क्योंकि ममता के मंच पर वामदलों के नेता नहीं पहुंचे थे। बंगाल के वामपंथी नेताओं का नारा है भाजपा हटाओ देश बचाओ और तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ। इसी नारे के साथ ब्रिगेड रैली में वामपंथी दलों का जमावड़ा होना है। माकपा की ब्रिगेड रैली में फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुजन आंदोलन के नेता एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाती प्रकाश यशवंत आंबेडकर को भी ब्रिगेड रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। जहां तक सवाल है शबाना आजमी को आमंत्रित करने का तो उनका परिवार कम्युनिस्ट आंदोलन के संपर्क में रहा है। शबाना आजमी के पिता एवं मशहूर गीतकार कैफी आजमी वामपंथी विचारधारा को मानने वाले थे। सवाल यह है कि जिस बंगाल में 34 वर्षों तक शासन करने वाला वामो आज चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। यहां तक कि मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। 2011 के बाद लगातार वाम दलों की जमीन खिसकती चली गई है। इस समय हर चुनाव में दूसरे स्थान पर भाजपा पहुंच चुकी है। ऐसे में ब्रिगेड रैली से लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा कामरेड भरते हैं और शक्ति प्रदर्शन का लाभ कितना होता है यह तो वक्त बताएगा?

दिशा सही मगर मंजिल दूर

डॉ. भरत झुनझुनवाला

तेज आर्थिक वृद्धि से जुड़े तथ्यों को देखते हुए हमें खुशी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अभी हम बहुत पीछे हैं

विश्व की प्रमुख सलाहकार संस्थाओं में शुमार प्राइसवाटरहाउस कूपर्स के अनुसार इस साल भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा भारत पहले ही हासिल कर चुका है। ये अनुमान देश की अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादन के आधार पर व्यक्त किए गए हैं जिसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना में केवल उत्पादन को ही मापा जाता है, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वह उत्पादन फायदे की सौगात बन रहा है या नुकसान का सबब। जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ गया तो अर्थव्यवस्था में उसके द्वारा किया जाने वाला 1000 रुपये प्रति दिन का उत्पादन कम हुआ और एक माह में जीडीपी 30,000 रुपये घट गया। वहीं दूसरी ओर उसकी सर्जरी के लिए चार लाख रुपये खर्च हुए। यह खर्च जीडीपी में जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से देश के जीडीपी में 3.70 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसी तरह मान लीजिए कि वायु प्रदूषण बढ़ गया। लोगों को दूध खरीदने के बजाय प्रदूषण से बचने के लिए मास्क खरीदने पड़े। ऐसे में जीडीपी पूर्ववत रहेगा, पर लोगों का जीवन स्तर गिर जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के परिदृश्य को समझना चाहिए।

वर्ष 2019 में भारत का जीडीपी लगभग 3,000 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो ब्रिटेन के 2,900 अरब डॉलर के जीडीपी से अधिक होगा। अब देखना है कि यह जीडीपी किस प्रकार के माल के उत्पादन से हासिल हुआ है। विश्व आर्थिक मंच यानी डब्लूईएफ द्वारा तैयार विश्व पर्यावरण सूचकांक में ब्रिटेन को 180 देशों में छठा स्थान दिया गया है जबकि भारत उसमें लगभग सबसे नीचे 177वें स्थान पर है। इसका अर्थ हुआ कि ब्रिटेन में दूध का सेवन ज्यादा हो रहा है जबकि भारत में एंटी-पॉल्युशन मास्क का। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ष 2019 में ब्रिटेन में उनतीस सौ अरब डॉलर के दूध का सेवन होगा जबकि भारत में तीन हजार अरब डॉलर के एंटी-पॉल्युशन मास्क की खपत होगी। लिहाजा हमें केवल बड़ी अर्थव्यवस्था बनने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने वाला एक अन्य पहलू जनसंख्या भी है। ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग सात करोड़ है और भारत की तकरीबन 136 करोड़। ब्रिटेन के इन सात करोड़ नागरिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 40,000 डॉलर की आय अर्जित की जाती है जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय का यही आंकड़ा लगभग 2,000 डॉलर है। भारत के नागरिकों की औसत आय ब्रिटिश नागरिकों की आय के बीसवें हिस्से के बराबर है, लेकिन भारत की जनसंख्या विशाल होने के कारण उसका जीडीपी अधिक हो जाता है। यह ऐसे हुआ कि 20 हिरनों का समूह एक हाथी से बोले कि हम तुमसे बड़े हो गए। जीडीपी का उल्लेख हम इसलिए करते हैं कि इसे देश के नागरिकों के जीवन स्तर का मानदंड माना जाता है। जीवन स्तर के मानदंड पर हम ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं। हमारा वर्चस्व विशाल गरीब जनसंख्या पर टिका हुआ है।

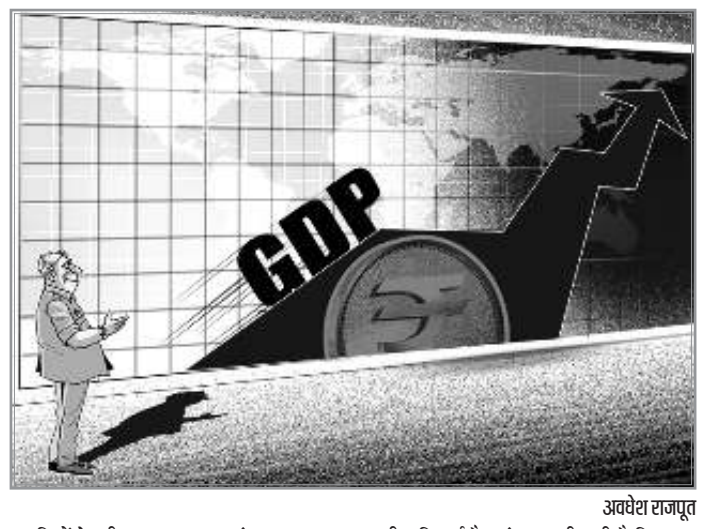

अवधेश राजपूत

अब जीडीपी की वृद्धि दर पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ के अनुसार 2018 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं चीन की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रह सकती है। निश्चित रूप से यह हर्ष का विषय है कि हमारी वृद्धि दर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम हो गई है, लेकिन इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। इसे एक अन्य उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक मजदूर की दिहाड़ी 300 रु थी। वह बढ़कर 400 रु हो गई। उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में मान लीजिए कि उसके मालिक की आय तीन करोड़ रु थी जो बढ़कर 3.3 करोड़ रु हो गई। इसमें मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार कहा जाएगा कि मजदूर की वृद्धि दर मालिक की वृद्धि दर से बहुत अधिक है। इतना सही है कि मजदूर की आय में 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, परंतु यह भी सही है कि 100 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में मालिक की आय में 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, परंतु राशि के आधार पर 30 लाख रुपये की भारी वृद्धि हुई है। जाहिर है केवल विकास दर पर ही बात करना उचित नहीं होगा।

यह विसंगति इसलिए पैदा होती है, क्योंकि 300 रु के छोटे आधार पर 100 रुपये की वृद्धि बड़ी दिखती है, जबकि तीन करोड़ के बड़े आधार पर 30 लाख की वृद्धि छोटी दिखती है। अतः सही तुलना समान आधार पर आंकी गई वृद्धि दर की होती है। जैसे दो मजदूर यदि 300 रु की दिहाड़ी प्राप्त कर रहे हों और एक की दिहाड़ी बढ़कर 400 रु हो जाए तो उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी और दूसरे की दिहाड़ी बढकर 330 रु हो जाए तो उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हो तब पहले मजदूर की वृद्धि दर निश्चित रूप से दूसरे मजदूर की तुलना में अधिक कही जाएगी। इस दृष्टि से हमें आज की अपनी आठ प्रतिशत की दुनिया में सबसे तेज गति से होने वाली वृद्धि को समझना होगा।

भारत का आज का जीडीपी चीन के 1990 के जीडीपी के लगभग बराबर है। चीन की 1990 तथा भारत की 2018 की तुलना सही होगी, क्योंकि इन वर्षों में दोनों का आधार लगभग एक समान था। चीन की 1990 में जीडीपी वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत थी जबकि 2018 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग आठ प्रतिशत है। अतः आज हमारी आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत होने से भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर विचार करना चाहिए कि इसी न्यून आधार पर जब चीन था तब उसकी वृद्धि दर हमसे बहुत अधिक 12 प्रतिशत के स्तर पर थी।

जीडीपी का एक और रहस्य यह है कि इसमें देश में वस्तुओं के उत्पादन की गणना की जाती है न कि देश के नागरिकों की आय की। मान लीजिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने देश में 100 रुपये के साबुन का उत्पादन किया और इसमें 20 रुपये का लाभ अपने मुख्यालय ब्रिटेन भेज दिया। ऐसे में जीडीपी में 100 रुपये की वृद्धि आंकी जाएगी, क्योंकि इतनी रकम के साबुन का उत्पादन हुआ, लेकिन आय में केवल 80 रुपये की ही वृद्धि होगी, क्योंकि 20 रुपये की आय बाहर चली गई। नागरिकों के जीवन स्तर का सही मापदंड देश की आय है न कि जीडीपी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में देश का जीडीपी 166 लाख करोड़ रुपये जबकि देश की आय 147 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जीडीपी की तुलना में हमारी आय 19 लाख करोड़ रुपये कम थी। जैसे गृहिणी ने 166 रुपये का भोजन बनाया, परंतु 19 रुपये का भोजन चूहे खा गए तो घर का शुद्ध भोजन मात्र 147 रुपये हुआ। हमारे सामर्थ्य एवं जीवन स्तर का सही मापदंड आय है न कि जीडीपी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमें खुशी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम बहुत पीछे हैं।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

सामाजिक प्रयोजनों से जुड़ता कुंभ

बद्री नारायण

धार्मिक उत्सवों में निहित विचारों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारों के साथ समायोजन के बिंदु तलाशने होते हैं

हिंदू धर्म के प्रत्येक आयोजन में कोई न कोई विचार छिपा होता है। यह विचार सेवा, दान, त्याग, एकता जैसे मूल्यों से जुड़ा होता है। अनेक बार संत-महात्मा, समाज सुधारक, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठन इन विचारों का उपयोग अपने पक्ष में एकता स्थापित करने और अपने मूल्यों को बल देने के लिए करते हैं। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होने वाले गणेश उत्सव को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने एवं आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के विचार से जोड़ने के लिए किया था। आज यह महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के अन्य भागों में भी एक बड़ा उत्सव बन गया है। धार्मिक उत्सवों में निहित विचारों को राजनीतिक विचारों के साथ समायोजन के बिंदु तलाशने होते हैं। जो विचारक, सुधारक या राजनीतिज्ञ धार्मिक उत्सवों में निहित विचार और अपनी संस्था या संगठन के विचारों के बीच समायोजन के बिंदु तलाशने में सफल हो जाता है वह धार्मिक उत्सवों को एक विचार के रूप में स्थापित करने की क्षमता भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है।

प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'दिव्य कुंभ-भव्य कुंभ' के रूप में प्रचारित किया है। इस कुंभ में राज्य सरकार पहले की भांति सिर्फ व्यवस्थापक की भूमिका में नहीं है। वरन वह साधु-संत एवं अखाड़ों को समायोजित करते हुए एक आयोजक की भूमिका में भी उभर आई है। भाजपा जैसी विचारधारा से लैस पार्टी की ओर से ऐसा किया जाना स्वाभाविक है। वास्तव में विचारधारा से युक्त पार्टी किसी भी आयोजन को अपने विचारों के अनुरूप ही संदर्भित करेगी। यह कुंभ एक अन्य मामले में भी पहले के कुंभ, अर्द्धकुंभ अथवा महाकुंभ से भिन्न दिखता है। जहां पहले के कुंभ एक धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव के तौर पर सीमित नजर आते थे वहीं इस बार इसे विचारों में बदलने का प्रयास भी दिखता है। इस अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें इस धार्मिक उत्सव को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों से जोड़ने की कोशिश दिख रही है। शायद इसी कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता के साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि विभिन्न दलों के नेता भी कुंभ पहुंच रहे हैं या फिर पहुंचने की तैयारी में हैं।

कुंभ के शुभारंभ के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों-मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद में अलग-अलग तरह के पांच विचार कुंभ आयोजित किए गए। इनमें अयोध्या का सद्भाव कुंभ, वाराणसी का पर्यावरण कुंभ, वृंदावन का महिला शक्ति कुंभ। लखनऊ का युवा कुंभ और प्रयागराज का समावेशी

कुंभ शामिल है। स्पष्ट है कि इनमें महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इन विचार कुंभों के माध्यम से आम लोगों को कुंभ में निहित पारंपरिक विचारों को आज के सवालों से जोड़ने की कोशिश की गई। यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न संस्थाओं ने कुंभ के प्रतीकों को अपने एजेंडे से भी जोड़ने की पहल की। उदाहरणस्वरूप सद्भाव विचार कुंभ में अलग-अलग सामाजिक समूहों के महत्व की चर्चा करते हुए उन्हें आदर देने का आह्वान किया गया।

सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के विचार का प्रसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे संबद्ध अन्य संगठन पहले से ही फैलाने में लगे हुए हैं। इसके तहत दलित एवं उपेक्षित सामाजिक समूहों को संघ के विचार परिवार से जोड़ने की कोशिश होती है। कुंभ के जरिये दलितों एवं अन्य वंचित समूहों के संग सहभोज और सह संवाद के तहत संघ द्वारा प्रस्तावित समाज-एकता में उनको नेतृत्व देने की भी कोशिश हो रही है। इसका लक्ष्य अपने वैचारिक मूल्यों के पक्ष में जागरूकता प्रसार है। यह उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक को भी राष्ट्रीय कुंभ का नाम दिया।

कुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पहले भी देखी गई है। इस बार वह प्रयागराज में भी नजर आ रही है। यहां राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े अनेक संगठन अपने शिविर लगाकर अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। विचार कुंभों के अतिरिक्त संघ और उससे जुड़े संगठन सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। जैसे कि नेत्र कुंभ का आयोजन। इसमें राष्ट्र और स्वास्थ्य के संबंधों को उजागर करते हुए दूर देहात से आए लाखों लोगों की आंखों की जांच की गई और उपचार के साथ चश्मे का वितरण भी किया गया। यह काम कितनी व्यापक तैयारी के साथ हुआ, इसका पता इससे चलता है कि स्वयंसेवकों ने गांवों, कस्बों, शहरों में घूम-घूम कर नेत्र रोगियों से फॉर्म भरवा कर उन्हें नेत्र कुंभ में आमंत्रित किया। इस कुंभ का उद्घाटन करते हुए विचार दृष्टि एवं नेत्र दृष्टि का समायोजन रेखांकित किया गया। कुंभ के दौरान विश्व हिंदू परिषद सदैव धर्म संसद का आयोजन करती रही है। इस बार भी ऐसा ही आयोजन होने जा रहा है। जाहिर तौर पर इसमें रामजन्म भूमि मंदिर मसले पर विचार होगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अन्य संगठन संस्कार भारती ने कुंभ का उपयोग देश की लगभग डेढ़ सौ नदियों के किनारे आयोजन कर इन नदियों को कुंभ में प्रतीकात्मक रूप में आमंत्रित करने के लिए भी किया। स्पष्ट है कि पहले डेढ़ सौ आयोजन, फिर कुंभ में इससे संबंधित कार्यक्रम कर संस्कार भारती एक बड़े जनमत तक पहुंची है। कुंभ में समरसता भोज के तमाम आयोजन अपनी-अपनी तरह से हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुंभ के प्रतीकों को अपने लक्ष्य एवं अभियानों के जोड़ने के अलावा इस अवसर का उपयोग अपने संगठनों को जागरूक करने के लिए भी किया है। इस तरह के आयोजन को संघ और उसके अन्य संगठनों को सशक्त करने का काम करेंगे। वे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उनकी पहुंच भी बढ़ाएंगे। यह देखना उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और उसके संगठन खुद को जनता से जोड़ने के लिए किस व्यापक स्तर पर सक्रिय हैं। कुंभ में हो रहे विभिन्न आयोजन केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विभिन्न संगठनों की समाज में पैठ तो मजबूत करेंगे ही, उनकी पहुंच और उनके प्रभाव का लाभ किसी न किसी रूप में भाजपा को भी मिलेगा। वैसे भी समरसता जैसे अभियान धार्मिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी असर दिखाते हैं।

(लेखक गोबिन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विश्व शांति

मेरी राय में परम सत्ता जहां बंधन से मुक्त है, उसे निर्गुण और जहां बंधनयुक्त है, उसे सगुण कहते हैं। सगुण में भी दो धारा हैं। एक रूपयुक्त और दूसरी अरूपयुक्त। मनुष्य में बुद्धि आदि जो अभौतिक तत्व हैं, वे अरूपयुक्त हैं। इसी तरह सगुण ब्रह्म भी अरूप है। इसी कारण हम उसे देख नहीं सकते। परमात्मा का चित्त रूपयुक्त है। यह परिदृश्यमान जगत परमात्मा का चित्त है। जहां सीमा का बंधन है, वहीं रूप है। जहां सीमा नहीं है, असीम है, वहीं अरूप है। जहां गुण है, उसे सगुण और जहां गुण नहीं है, उसे निर्गुण कहते हैं। यह विश्व परमात्मा के चित्त की सृष्टि है। यह सृष्टि रूपवान है, इसलिए इसमें सीमा है। मनुष्य परमात्मा की कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि वह उसके चित्त से बड़े हैं। मन में जो अहंतत्व है, वह भी अरूपयुक्त सगुण है। यह जो अरूपयुक्त सगुण है, उसका विषय सीमित चित्त है।

साधना के दौरान ऐसी स्थिति आती है, जब साधक का मन सगुण ब्रह्म के मन जैसा हो जाता है और उसकी आत्मा परम चेतना बन जाती है। इसलिए इसे सगुण साधना कहते हैं। सगुण उपासना का अर्थ साकार की उपासना कदापि नहीं है। यह जो अरूपयुक्त गुणवान मानवमन है, उसके चित्त का विषय जितना बड़ा होगा, उसी के अनुसार उसकी श्रेष्ठता निर्धारित होगी। इसलिए साधना मन के विषय को बड़ा बनाना है। परमात्मा के लिए हिंदू-मुसलमान-सिख-ईसाई आदि सब समान हैं। साधक का देश है विश्व-ब्रह्मांड और जाति है जीव मात्र। धार्मिक साधकों और संगठनों को समस्त विश्व को अपना विषय क्षेत्र बनाना चाहिए। जो लोग विश्व की एकता का प्रचार करते हैं, परंतु मन में क्षेत्रवाद, जिलावाद, प्रांतवाद और जातिवाद आदि को प्रश्रय देते हैं, वे कपटी हैं। साधक को यह समझना चाहिए कि यह विश्व मेरा है और हम विश्व के हैं। जो ऐसा नहीं मानेंगे, उन्हें अंततः इस सत्य को मानना पड़ेगा।

समाज मनुष्य की सामूहिक संस्था है। जब तक मनुष्य विश्व-एकतावाद को नहीं अपनाएगा, तब तक अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आदर्श की भिन्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न समाज बनते रहेंगे। विश्व शांति के लिए एक आदर्श लेकर चलना होगा और वह आदर्श है हिंसारहित तथा अराजकतारहित व्यवस्था का नवनिर्माण। इसी से धर्म की प्रतिष्ठा होगी।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

कितना सफल है हमारा लोकतंत्र

रिजवान अंसारी

विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय का 22 फीसद भाग सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में पहुंचता है

हाल ही में लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के 167 देशों के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक-2018 जारी किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की पड़ताल की गई है। इसमें नॉर्वे को पहले पायदान पर रखा गया है, जबकि उत्तरी कोरिया को अंतिम पायदान पर जगह मिली है। जहां तक भारत का सवाल है तो 167 देशों की सूची में भारत को 41वें पायदान पर जगह मिली है।

दुनिया के 167 देशों को चार तरह के शासन मसलन-पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन और सत्तावादी शासन में बांटा गया है। इसमें चिंता की बात है कि 167 देशों में महज 20 देशों को पूर्ण लोकतंत्र वाला देश बताया गया है और इसके तहत 167 देशों की महज 4.5 फीसद आबादी शामिल है। सबसे ज्यादा 43.2 फीसद आबादी दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में बसती है और यह कुल 55 देशों में फैली है जिनमें एक देश भारत भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत का लोकतंत्र सफल नहीं है? सवाल यह भी है कि भारत के सामने ऐसी कौन-सी चुनौतियां हैं जो उसे पूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आने से रोक रही हैं? दरअसल इस रिपोर्ट में भारत सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव पर चिंता जताई गई है। साथ ही किसान, रोजगार और संस्थागत सुधार के मामले में भारत सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया गया है। यही वजह है कि भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।

भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, इसका फैसला करने के लिए विगत सत्तर वर्षों के इतिहास, देश की उपलब्धियां, देश के विकास, सामाजिक-आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की जरूरत है। दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लिंग भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है।

अगर भारत के संदर्भ में इन्हीं पहलुओं पर गौर करें तो स्थिति चिंताजनक दिखती है। देश में भुखमरी और कुपोषण एक सामान्य बात है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक निचले स्तर की जीवनशैली और स्वास्थ्य-सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते नागरिकों की संख्या करोड़ों में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 36 करोड़ आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। दूसरी तरफ देश का एक तबका अच्छी सुख-सुविधाओं से लैस है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसद भाग सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में पहुंचता है और यह असमानता लगातार बढ़ रही है। बहरहाल लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिए जरूरी है कि पहले बुनियादी समस्याओं को हल किया जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

नीतिपरक राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण

हृदयनारायण दीक्षित ने अपने आलेख 'गुमनाम नायकों का सम्मान' में यह ठीक ही कहा है कि देश के कर्मयोगियों का सम्मान करना राष्ट्र का दायित्व है, जिसे मोदी सरकार ने भेदपरक राजनीति से ऊपर उठकर निर्वाहित किया है। निष्काम भाव से समाज-सेवा में रत रहने वाले महान कर्मयोगी नानाजी देशमुख और अपनी सांस्कृतिक साधना से गीत-संगीत की दुनिया में ख्याति अर्जित करने वाले भूपेन हजारिका के साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी को भी भारत-रत्न से विभूषित करना मोदी सरकार की नीतिपरक राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। राष्ट्रनीति से रहित देश की राजनीति से राष्ट्र-विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से आजाद भारत में एक लंबे समय तक राष्ट्रनीति को दरनिकार कर स्वयं को पोषित करने वाली राजनीति का विकृत खेल, खेला जाता रहा है। जिसके दुष्परिणाम स्वरूप विशाल जन-शक्ति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला भारत आज तक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, जबकि भारत से बहुत छोटे फ्रांस और जापान जैसे देश अनेक विषमताओं के बाद भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के विभेदों में उलझने वाली भारत की राजनीति उस राष्ट्रीय चेतना को उद्भासित नहीं कर पाई, जिसकी जरूरत थी। आज एक लंबे समय के बाद देश ने इस बात को महसूस किया है कि तमाम विभेदों के बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि है।

pandeyvp1960@gmail.com

दलों के सियासी दांवपेच

चुनाव का बिगुल बजने से ऐन पहले दलों के सियासी दांव-पेच से जाहिर है कि हर किसी को बाजी अपनी तरफ मोड़ने की बेताबी है। देश का हर छोटा-बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से खास है, मगर उत्तर प्रदेश की खास अहमियत है। कहते हैं कि दिल्ली की दावेदारी यहां के 80 लोकसभा सीटों से तय होती है। नेहरू-गांधी परिवार का इस राज्य से खास नाता है। अब प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की घोषणा से बयानों की धार और तेज हो गई है। भले ही प्रियंका ने अब तक कोई बयान न दिया हो, लेकिन उनको लेकर अच्छी-खासी बहस छिड़ी हुई है कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हफ्ते-दो हफ्ते में जब भी उनका बयान आएगा तब कुछ साफ होगा कि वह विरोधी दलों पर कितनी आक्रामक हैं।

mkmishraz@yahoo.in

राजनीति में शिक्षा

मप्र की एक मंत्री गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश तक ठीक से नहीं पढ़ पाईं और उस संदेश को कलेक्टर को पूरा करना पड़ा। पूर्व में वह शपथ भी ठीक से नही ले पाई थीं और अटक-अटक कर उन्होंने बात पूरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार चिंता व्यक्त की थी कि राजनीति में प्रतिभा की कमी है। जब इतना सब कुछ पता है तो सरकार क्यों नहीं राजनीति में शिक्षा की सीमा की नीति लागू कर पा रही है? एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और शिक्षा की सीमा जरूरी है तब प्रदेश व देश चलाने के लिए आखिर शिक्षा और पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस की जा रही है? सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को अपनी पार्टी की छवि उज्ज्वल करने के लिए स्वच्छ छवि वाले और प्रतिभावान व पूर्ण शिक्षित लोगों को प्रवेश देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे प्रतिभाओं को सम्मान मिलेगा, राजनीतिक छवि सु